प्रेषक,

रविनाथ रामन, सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में.

जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादूनः दिनांक 1/3 अप्रैल, 2022

विषय:-यूजेवीएन लिमिटेड गुप्तकाशी जल विद्युत परियोजना की भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में। महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या—1457/26—03 (2021—22), दिनांक 20 दिसम्बर, 2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से निम्नलिखित तालिका में अंकित कुल—11 खसरा नम्बरानों में 0.669 है0 राज्य भूमि यूजेवीएन लिमिटेड के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण करने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है:—

<b>क</b> 0 सं0	ग्राम का नाम	NZA खतौनी खाता संख्या	खसरा संख्या–	सम्पूर्ण क्षेत्रफल (हैक्टेयर) में	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हैक्टेयर) में	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7
1.	ल्वारा	59	1674	1.761	0.060	श्रेणी—10(4) अन्य कारणों से अकृषिक भूमि चट्टान
2.	ल्वारा	59	1703	0.198	0.010	- <del>-</del> <del>-</del> <del>-</del> <del>-</del>
3.	ल्वारा	59	1704	0.178	0.015	-4-
4.	ल्वारा	59	1705	0.069	0.015	-6-
5.	ल्वारा	59	1706	1.203	0.080	-0-
6.	जमलोक	04	175	0.113	0.040	श्रेणी-9(3) अन्य कारणों से बंजर भूमि
7.	जमलोक	04	177	0.547	0.090	-ए-
8.	धारसेमी	11	10	7.733	0.200	श्रेणी—10(4) अन्य कारणों से अकृषिक भूमि चट्टान
9.	धारसेमी	11	45	0.088	0.039	-0-
10.	सेमतल्ली	13	938	0.060	0.020	श्रेणी—10(4) अन्य कारणों से अकृषिक भूमि (रौली)
11.	सेमतल्ली	21	930	0.217	0.100	श्रेणी—10(1) अन्य कारणों से अकृषिक भूमि भीटा (जलमग्न)
योग–			11	12.167	0.669	

- 2— उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त तालिका में अंकित कुल—11 खसरा नम्बरानों में 0.669 है0 राज्य भूमि गुप्तकाशी (1.5 मेगावाट) लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या—496/XVIII(II)/2020—08(63)/2020, दिनांक 28 जुलाई, 2020 में निहित व्यवस्थानुसार श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन यूजेवीएन लिमिटेड के पक्ष में सःशुल्क पट्टे पर आवंटित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—
- (1) प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमित प्राप्त कर ली जायेगी। जिलाधिकारी पहले इसे सुनिश्चित करेंगें। तद्नुसार वन विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही पट्टा निष्पादन की कार्यवाही करेंगे।
- (2) चूंकि जिलाधिकारी द्वारा संबंधित शासनादेश दि0-09-05-1984 के अधीन निर्धारित प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्राविधानों का अनुपालन अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।
- (3) इस संबंध में सिविल अपील संख्या—1132/2011(एस0एल0पी0)/(सी) संख्या—3109/ 2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (4) प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत प्रदान की गयी है।
- (5) प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने का अधिकार पट्टेदार को नहीं होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 वर्ष की अविध में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा तथा उक्त भूमि भार सहित राज्य सरकार में निहित हो जायेगी।
- (6) प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को नहीं रह जायेगी तो भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।
- (7) यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संस्था का विघटन हो जाता है तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।
- (8) भू—उपयोगिता व पट्टे में इंगित शर्तों के कम में शासन/जिलाधिकारी/अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकता है।
- (9) निगम द्वारा शासनादेशानुसार नजराने एवं मालगुजारी की जमा करायी गई धनराशि की प्राप्ति रसीद/चालान की प्रति तत्काल शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3— कृपया इस सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश एवं इस शासनादेश की शर्तों की अनुपालन स्थिति से भी अनिवार्य रूप से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(रविनाथ रामन) सचिव।

## संख्या-188/xvIII(II)/2022 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव / सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
- 5— अधिशासी अभियन्ता (जनपद-प्रथम), यूजेवीएन लिमिटेड, कुण्ड, गुप्तकाशी।
- 6— महाप्रबन्धक (ल०ज०परि०) "उज्जवल" महारानी बाग, जी०एम०एस० रोड़, देहरादून।
- 7- निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय, देहरादून।

🥦 गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

्गीता शरद) अनु सचिव।